SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I said that, at this point of time, there are ten types of standards laid down. According to those specifications, packaging material is to be used. Globally, the standards are maintained accordingly, and India also does so. As far as leaching and other things are concerned, it affects only when we do not maintain the standards. If it is below 60 parts per million, it does not affect. So, that is what we have to keep in mind.

Engaging young boys and girls in various sports

*242. KUMARI SELJA: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) the scheme/programme initiated for development of structured system at the grass-root level to engage young boys and girls in the age group of 10-14 in various sports;

(b) whether measures are being taken for ensuring availability of sporting equipments and wholesome nourishment to identified sportspersons; and

(c) whether measures are being taken to set up Sports Science and Sports Medicine Centres to support the sports fraternity, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry of Youth Affairs and Sports is implementing a scheme, namely, "Khelo India – National Programme for Development of Sports" with effect from the year 2016-17. Among other things, this scheme aims at conducting annual sports competitions in three age categories, *i.e.*, Sub-junior, Junior and Senior, to encourage mass participation of children in Sports. The age group for these three categories varies in respect of different sports disciplines. The Ministry, through the Sports Authority of India (SAI), is also implementing the following Sports Promotional Schemes for development of structured system at grass-root level to engage young boys and girls in the age group of 10-14 in various sports:

(i) National Sports Talent Contest Scheme (NSTC)

(ii) Army Boys Sports Company (ABSC)

(iii) SAI Training Centre (STC)

(iv) Special Area Games (SAG)

(v) Extension Centre of STC/SAG

(vi) Centre of Excellence (CoE)

(vii) National Sports Academies (NSA)

In order to promote sports across the country, SAI has established 12 Regional Centres/Academic Institutions having International Standard Sports infrastructure alongwith other allied facilities to train the potential athletes selected from their jurisdictional States. To ensure availability of wholesome nourishment to identified sportspersons, details of measures being taken are given in Statement-I (*See* below).

(c) The Ministry of Youth Affairs and Sports already has Sports Science/Sports Medicine Centres in the Regional Centres and Academic Institutions of SAI. Details are given in Statement-II.

Statement-I

Details of measures being taken to ensure availability of wholesome nourishment to identified sportspersons

(i) The nutrient intake of the sportsperson is being studied and thereafter sports specific diet plans are prepared and implemented in SAI centres.

(ii) Nutritionists are attached to National camps in various SAI Centres to provide technical support and diet management to the sportspersons.

(iii) Research fellows have been inducted to strengthen research in Sports Nutrition.

(iv) Regular revision of diet plans at different levels including National Campers, CoE.

(v) Standardization of recipes and planning sport specific diets.

(vi) Developed Education material for Athletes based on the inputs and assessments during diet counseling sessions.

(vii) Large scale dissemination of nutrition education is taken up through articles on sports nutrition in Utkarsh, SAI Newsletter.

(viii) Regular Individual and Group Counseling sessions are taken up for athletes in SAI centres.

(ix) Procurement of Equipment to evaluate the nutrient requirement of players is in progress.

(x) Procurement of Sports Medicine and Sports Science Equipment for SAI centres at Delhi, Patiala, Bangalore, Sonepat, Bhopal, Jagatpur, Aurangabad, Gandhinagar and Lakshmibai National College of Physical Education

(LNCPE), Thiruvananthapuram is commissioned from Head office and the centres are optimally equipped to provide scientific support to sportspersons.

Statement-II

Details of Sports Science/Sports Medicine Centres in the Regional Centres and Academic Institutions of SAI

The following Regional Centres and Academic Institutions under Sports Authority of India have Sports Science/Sports Medicine Centres:

1. SAI Netaji Subhash National Institute of Sports (NSNIS), Patiala.
2. SAI Netaji Subhash Eastern Centre (NSEC), Kolkata.
3. SAI Netaji Subhash Southern Centre (NSSC), Bangalore.
4. SAI Head Quarters, Delhi.
5. SAI Netaji Subhash Western Centre (NSWC), Gandhi Nagar.
6. Lakshmibai National College of Physical Education (LNCPE), Thiruvananthapuram.
7. SAI Central Centre, Bhopal.
8. SAI Regional Centre, Lucknow.
9. SAI Northern Centre, Sonepat.
10. SAI Netaji Subhash North-East Regional Centre (NSNERC), Imphal.
11. SAI Regional Centre (RC), Guwahati.

SHRI JAYANT SINHA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is in Rio with the Olympic contingent, so, I shall be answering the questions on his behalf.

कुमारी शैलजाः सर, माननीय खेल मंत्री जी रियो गए हैं, जैसा बताया गया है, let us hope कि उनकी हौसला अफजाई से we win some medals and performance is improved by his presence there.

सर, मैंने छोटे बच्चों के बारे में जो सवाल पूछा, from the age group of 0 to 14, आप यह मानेंगे कि आपने संस्थाएँ तो set up की हैं, वह एक अलग बात है और अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर छोटे बच्चों की nurturing स्कूल में ही नहीं होगी, तो ये competitions, ये institutions, ये संस्थाएँ, ये सब बेमानी हो जाएँगी। स्कूलों में, जहां पढ़ाने के लिए टीचर्स तक नहीं हैं, वहां पर बच्चों को खेल-कूद में आगे कैसे बढ़ाया जाए, वहीं पर बच्चों की प्रतिभा को कैसे समझा जाए, उनको कैसे nurture किया जाए, उनको वहां पर कैसे equipment दिया जाए, इन सब बातों के लिए grassroot level पर, गांवों के स्कूलों में और शहरों के प्राइमरी स्कूलों में सरकार क्या कर रही है?

श्री जयंत सिन्हाः सभापति महोदय, माननीया सदस्या ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम लोगों को ओलंपिक जैसे competition में अच्छा करना है, तो हम लोगों को बिल्कुल कम उम्र से बच्चों को सभी resources, सभी साधन देने चाहिए। इसके तहत सरकार ने 'खेलो इंडिया' के द्वारा और सभी राज्यों के सहयोग के साथ कोशिश की है कि जिला स्तर पर जितनी सुविधाएँ, जितने साधन हम दे सकते हैं, हम जरूर दें। जिला स्तर पर competition हो और competition में जो सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका चयन करके उनको जो भी सुविधाएँ हों, चाहे वे nutrition की सुविधाएँ हों या facilities की सुविधाएँ हों या कोचिग की सुविधाएँ हों, हम इन सुविधाओं का प्रावधान करें, जिससे वे उभर कर आएँ और देश का तिरंगा ओलंपिक जैसे competition में बिल्कुल ऊँचा हो जाए।

कुमारी शैलजाः सर, मेरा यह सवाल नहीं था। मैंने खुद यह बात कही कि ये सब चीजें तो हैं, लेकिन अगर स्कूलों में छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, अगर उनकी प्रतिभा मालूम ही नहीं पड़ेगी, इसके लिए स्कूल में क्या किया जा रहा है, लेकिन मैं press नहीं करूँगी, क्योंकि यह मंत्रालय माननीय मंत्री जी का नहीं है, वे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल यह है, I have not understood the reply given in Statement-I. अब यह अंग्रेज़ी खराब है, या यह क्या बताना चाह रहे हैं? "Part I - the nutrient intake of the sportspersons is being studied, and, thereafter..." I do not understand this. Please आप इसको clarify करिएगा। I am coming to my supplementary. जहां तक सपोर्टिंग इक्यूपमेंट की बात है, रियो ओलम्पिक में, जैसा हम टीवी पर देखते हैं, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यूज़ आते हैं, हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कहा कि वहां पर जो सुविधाएं हैं, हालांकि I am not saying that we are responsible, वह तो वहां के host country की बात है कि जो सीडब्लूजी में सुविधाएं थीं, जो फैसेलिटीज़ थीं, They were far superior, बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिली थीं, बजाय रियो के। वहां पर उनको सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। इसके साथ ही एक जुड़ी हुई बात यह है कि उन्होंने इक्युपमेंट की बात भी कही कि चूंकि international Olympic level पर international standard पर कम्पीट करना होता है, तो इस बार भी उनको वहां ओलम्पिक में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों सब-स्टैंडर्ड इक्युपमेंट मुहैया कराया गया? वहां पर चाहे मंत्री जाएं, चाहे ऑफिशियल्स जाएं, उनके जाने का कोई मतलब नहीं होगा, अगर सब-स्टैंडर्ड इक्युपमेंट देकर उन्हें वहां पर कम्पीट करने के लिए भेजा जाता है। इसके बारे में आपका क्या जवाब है?

श्री जयंत सिन्हाः सर, माननीय सदस्या को मैं थोड़े से और आंकड़े देना चाहूंगा। पिछले जवाब के लिए, जैसा वे कह रही थीं कि मुझे उसमें थोड़ा और व्यापक रूप से जवाब देना चाहिए, फिर जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तहत मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक नेशनल स्पोर्ट्स टेलेन्ट कांटेस्ट हो रहा है, जिसके जरिए खासकर जो आठ से चौदह साल के बच्चे हैं, उनको जिला-स्तर पर हम प्रोत्साहन देंगे। इसी तरह एक आर्मी बॉएस स्पोर्ट्स कंपनी का भी एट टू सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड का कॉम्पिटिशन चलता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 58 ट्रेनिग सेंटर्स है, उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि स्टेट लेवल पर जो किया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. ...(*Interruptions*)... Let him finish. ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः मैं जवाब दे रहा हूँ, आप संतुन्ट होंगी, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** राज्य जो कर रहे हैं और गुजरात जैसे राज्य हैं, जिनका बजट ही स्पोर्ट्स के लिए पांच सौ करोड़ रुपए है, तो वहां बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। **...(व्यवधान)...**

कुमारी शैलजाः सर, यह क्या जवाब दे रहे हैं? **...(व्यवधान)..**

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः स्कूलों को बहुत साधन दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसको सप्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स ऑथिरटी ऑफ इंडिया का जो "खेलो इंडिया" कार्यक्रम है, उससे सप्लीमेंट कर रहे हैं और यह जिला-स्तर पर हो रहा है। फिर माननीया सदस्या का दूसरा प्रश्न था कि जिस ओलम्पिक क्वालिटी फैसेलिटीज का सीडब्लूजी वगैरह में प्रयोजन किया गया था, किस तरीके से उसको और बेहतर बनाकर लोगों के लिए प्रावधान कर रहे हैं, तो माननीय सदस्या को मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें से पांच हो चुके हैं। साइकलिंग, इंदिरा गांधी स्टेडियम में साइकलिंग वेलोड्रोम है, वहां हैं, स्विमिंग का तालकटोरा स्टेडियम में है और **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please. Just a minute. ...(*Interruptions*)... Be patient. Just be patient. Let him finish, please.

श्री जयंत सिन्हाः ये सीडब्लूजी की फैसेलिटीज़ हैं।

KUMARI SELJA: Sir, it is not my question. ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी ये फैसेलिटीज़ दी जा रही हैं।

KUMARI SELJA: It is not the answer. What is he saying? ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः एथलेटिक्स के लिए तिरुवनंतपुरम में है और मिडल डिस्टेंस एथलेटिक्स के लिए भोपाल में है, गोल्फ के लिए **...(व्यवधान)...**

KUMARI SELJA: I never asked this. ...(*Interruptions*)... Sir, I need your protection. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAYANT SINHA: Thirteen other national academies... ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I need your protection. ...(*Interruptions*)... I never asked this. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAYANT SINHA: ...using the best Olympic facilities are also being provided. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, if the answer is unsatisfactory, please take it up in writing. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: As I said, ... (*Interruptions*)... सर, सवाल कुछ पूछ रहे हैं और जवाब कुछ आ रहा है।

MR. CHAIRMAN: I am telling you the procedure. You have a written answer. Now, if the answer is unsatisfactory, please take it up.

कुमारी शैलजाः सर, आप मुझसे कह रहे हैं, आप मंत्री जी से भी कह सकते हैं। As I said, he is not dealing with it; it is okay. सर, इतना तो न करें, गुजरात का यहां बजट कहां से आ गया? गुजरात ने कभी कोई मैडल जीता है? कुछ बताएं तो सही।

MR. CHAIRMAN: Just listen to me. ...(*Interruptions*)... One minute. If a Member expresses in writing discontent with a written answer, then, that, in itself, is a serious enough matter because it will elicit a more reasoned response from the Government. So, you have made your point, you are not satisfied with the answer. Please take it up in writing and point out specifically where the answer is wrong so that the Government is able to answer.

कुमारी शैलजाः सर, मैं written की बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी मैंने सप्लीमेंटरी सवाल पूछा, उसके जवाब की बात कर रही हूँ। यहां गुजरात का बजट कहां से आ गया?

डा. सत्यनारायण जटियाः माननीय सभापति जी, हम रियो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, हमारे सामने 'खेलो इंडिया' लक्ष्य है। हम साई सेंटर्स की बात करते हैं, ये सब सेंटर्स विकसित होने की स्थिति में हैं। हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो 10 से 14 साल के हैं। जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको पढ़ना भी पड़ता है और हम उनको खेलने के लिए भी कहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे, जिससे उनका भविष्य और आजीविका सुरक्षित हो सके, उनको अपना भविष्य निर्माण करने में सहायता मिल सके और इसके साथ ही वे खेल में और पारंगत हो सकें, क्या ऐसी प्रतिभाओं की तलाश करके ऐसे खेल स्कूल, जैसे हम सैनिक स्कूल बनाते हैं, उसी प्रकार से खेल स्कूल की स्थापना करने की दृष्टि से सरकार विचार कर रही है?

श्री जयंत सिन्हाः सर, सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 'खेलो इंडिया' में यही कोशिश रही थी कि जो तीन अलग-अलग किस्म की स्कीम्स थीं, उनको जोड़ कर एक consolidated scheme हो, जिसमें कि जो स्टेट्स में किया जा रहा है, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, उसको supplement किया जाए। जो आधुनिक से आधुनिक facilities, कोचिंग के जो तरीके होते हैं, वे सब हम उनको दें। इसके साथ ही जिला स्तर पर competition होना चाहिए, उसके द्वारा हम लोग टैलेंट्स का चयन करें और उन टैलेंट्स को जो भी साधन चाहिए, यानी स्पोर्ट्स अकेदमी में और स्कूल्स में जो साधन चाहिए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आर्मी के साथ, आर्मी के सहयोग से भी काम कर रहे हैं। उन्होंने 18 ऐसे आर्मी स्पोर्ट्स स्कूल्स तैयार किए हैं, जहां लोगों को ट्रेनिग दी जा रही है। जो साई स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, वहां पर करीब 11-12 हजार ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया है और उनको वहां पर intensive training दी जा रही है। यह कोशिश है कि जो स्टेट्स कर रही हैं और इसलिए मैंने स्टेट के बजट के बारे में जिक्र किया, स्टेट्स के बजट भी काफी होते हैं, उनके भी magnitude

[श्री जयंत सिन्हा]
काफी होते हैं। उनके सहयोग के साथ केंद्र सरकार मेहनत कर रही है, जिसमें हमारे सारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को सब facilities मिलें।

श्रीमती कहकशां परवीनः माननीय सभापति महोदय, 10 से 14 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के बारे यह सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा रहती है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी कोई योजना है, जिसके द्वारा ऐसे बच्चों को खेल-कूद में अवसर मिले?

श्री जयंत सिन्हाः सर, हम लोगों की बिल्कुल यह कोशिश है कि जिन बच्चों में स्पोर्ट्स की प्रतिभा है, उनको नेशनल टैलेंट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाए। इसी कारण हम लोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कई तरीके के competitions कर रहे हैं, स्टेट्स अपने competitions कर रही हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स हैं, वे अपने competitions कर रहे हैं और इस तरीके से meritocratic process के द्वारा जिन लोगों का मेरिट है, जिनकी प्रतिभा है, उन लोगों का चयन किया जाए, उसके बाद उन लोगों को सब सुविधाएं दी जाएं। इसमें हम लोग लगे हुए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, जिसके तहत हमने कई लोगों को स्कॉलरशिप दिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। मैं आपको इसके आंकड़े बता दूं कि आज तक कितने बच्चों को यह दिया गया है। कुल मिला कर 11,773 talented sportspersons, 8,243 boys and 3,530 girls, are being trained in 27 sports disciplines under residential and non-residential basis in 251 SAI Centres. इस तरीके से लोगों को ये facilities दी जा रही हैं।

श्री पी. एल. पुनियाः सभापति जी, यह सवाल 10 साल से 14 साल के बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने के बारे में है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में योजनाओं का भी उल्लेख किया है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम, सेना बाल खेल कम्पनी स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम आदि स्कीमों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन स्कीमों के तहत पिछले दो वर्षों में कितने बच्चों को प्रशिक्षित किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

श्री जयंत सिन्हाः सर, मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 11,773 स्पोर्ट्स पसर्न्स को स्कॉलरशिप दी गई है और उन लोगों को इसके द्वारा बहुत फायदा हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरीके से हमारी सरकार स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रही है, हम लोगों का इस समय ओलंपिक का जो contingent है, वह 118 खिलाड़ियां का है, जब कि पिछली बार, यानी 2012 में 81 खिलाड़ियों का था। We have gone from 81 sportspersons to 118 sportspersons which is a growth of 50 per cent. We have provided them with very specialised customised training. We have selected 26 foreign coaches to be able to provide them this kind of support. हम लोग जो-जो facilities दे सकते हैं, वे हम लोग दे रहे हैं।

आपने यह भी पूछा कि इस पर कितना खर्च हो रहा है, कितनी राशि जा रही है? 'खेलो इंडिया' का जो कार्यक्रम है, उस पर 140 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। जो SAI सिस्टम है, उसमें कुल मिलाकर 451 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, जिसमें से 345 करोड़ रुपया प्लान

एक्सपेंडिचर है और 71 करोड़ रुपया नॉन-प्लान एक्सपेंडिचर है। जो NSDF है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, उसमें विशेष रूप से जो हमारे टॉप प्रोग्राम्स हैं, जो टॉप ओलम्पियन्स हैं, उन लोगों को हम सहयोग देते हैं। उसमें 115 करोड़ रुपये की राशि है।

Financial assistance to NE States

*243. SHRI SHANTARAM NAIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the pattern of financial assistance given to the North-Eastern States from the year 2014;

(b) what was the formula adopted prior to 2014;

(c) the reasons for change in the pattern of assistance made, including the assistance given under Central Schemes;

(d) whether any notification has been issued in this regard; and

(e) if so, text of the notification?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Following the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, devolution to the States was increased from 32% to 42%. The horizontal formula adopted by the Fourteenth Finance Commission, for distribution of the divisible pool, among the States is based on the following variables: Population (1971): 17.5%, Demographic Change (1971-2011): 10%, Fiscal capacity/Income distance: 50%, Area: 15%, Forest cover: 7.5%. This led to an increase in the transfer to States from ₹ 337808 crore in 2014-15 to ₹ 523958 crore in 2015-16 (BE), an increase of ₹ 186150 crore.

Due to resulting paucity of resources with the Centre, some schemes were delinked from the Union support and funding pattern for some Centrally Sponsored Schemes was changed. A Sub Group/Committee of Chief Ministers was constituted by NITI Aayog to rationalize Centrally Sponsored Schemes and to recommend the revised funding pattern. The following recommendations have been accepted by the Government.

(i) Core of the Core schemes: funding pattern remains unchanged

(ii) Core schemes: 90:10 for North Eastern States

(iii) Optional schemes: 80:20 for North Eastern States